

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर रायिव,
उत्तरांचल शासन ।

रोवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग-२

देहरादून: दिनांक २५ अक्टूबर, २००५

विषय:- ग्रामीण पेयजल राज्य सौवटर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा एवं नैनीताल की भतरौंज रीची थापला ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या १५०/अप्रेजल-अल्मोड़ा/दिनांक ०२.०४.२००५ के सन्दर्भ में गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष २००५-०६ में ग्रामीण पेयजल राज्य सौवटर के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा एवं नैनीताल की भतरौंज रीची थापला ग्राम समूह पेयजल योजना के रु० ९४५.९२४ लाख के आगणन के टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई रु० ८७९.४५ (रु० आठ करोड़ उन्नासी लाख पैतालीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (१) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (२) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।
- (३) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्ग है, स्वीकृत नार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।
- (४) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- (५) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय ।

(6) कार्य करने से पूर्व स्थल की भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाले सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9) कार्यों में सैंटेज/कन्टीजैन्सी व्यय वर्तमान में प्रचलित शासकीय दर से नियमानुसार ही लिया जायेगा।

(10) योजना को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित प्रावकलन स्वीकार्य नहीं होगा।

(11) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ग्राम सभाओं/वन भूमि का हस्तान्तरण विधिवत पूर्ण करा लिया जाय।

12— योजना के अन्तर्गत 0.60 हैक्टेयर वन भूमि क्षेत्र है और शेष भूमि ग्राम सभाओं से निःशुल्क प्राप्त होनी है। अतः धनराशि की स्वीकृति के पूर्व उपरोक्त दोनों कार्यवाही पूर्ण करके शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं०-39/XXVII(3)/2005 दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

सं०/०७३/उन्तीरा(2)-2(12पे०)/2005, तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।
2. मण्डलायुक्त कुमाँयू।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
5. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तरांचल पेयजल निगम, रामनगर को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गई कटौतियों का विवरण नोट करने हेतु निर्देशित करें।
6. वित्त अनुभाग-3/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रानीलश्री पांथरी)
अनु सचिव